1. भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (India's Updated Nationally Determined Contribution (NDC))

1.1. NDC क्या है?

- NDC कार्बन उत्सर्जन में कटौती और जलवायु प्रभावों के अनुकूल दीर्घकालिक लक्ष्यों का एक सेट है जिसे पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक देश को प्रदान करना होता है, और हर पांच साल में अद्यतन करना होता है।
- पेरिस समझौते के धारा 4, उपधारा 2 में कहा गया है कि 'प्रत्येक पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को तैयार करेगा, संचार करेगा और बनाए रखेगा जिसे वह हासिल करना चाहता है। पार्टियां ऐसे योगदान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से घरेलू शमन उपाय अपनाएंगी।'
- समझौते के तहत, पार्टियों को हर पांच साल में अपने NDC को अपडेट करते रहना होगा और इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के सचिवालय को जमा करना होगा।

1.2. पृष्ठभूमि

- भारत पेरिस समझौते के 195 पार्टियों में से एक है, जो जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- इससे पहले, भारत ने 2 अक्टूबर 2015 को आठ मुख्य लक्ष्यों के साथ अपना इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC) UNFCCC को प्रस्तुत किया था।
- इनमें से तीन का मात्रात्मक लक्ष्य 2030 तक है, अर्थात्,
    - गैर-जीवाश्म स्रोतों से संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता 40% तक पहुँचना;
    - 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना
    - अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण।

1.3. भारत के अद्यतन NDC का परिचय

- अगस्त 2022 में, भारत ने औपचारिक रूप से अपने NDC को UNFCCC में अद्यतन किया, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।
- अद्यतन NDC 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक कदम है।
- यह पेरिस समझौते के तहत सहमति के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने की उपलब्धि में भारत के योगदान को बढ़ाने का प्रयास करता है।

1.4. भारत के अद्यतन NDC का मुख्य प्रावधान

- भारत अब 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत (पहले INDC में उल्लिखित 33-35% सीमा से अधिक) कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- भारत 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता भी हासिल कर लेगा (पहले INDC में यह लक्ष्य 40% था)।
- अद्यतन NDC ने संरक्षण और संयम की परंपराओं और मूल्यों के आधार पर जीवन जीने का एक स्वस्थ और सतत् तरीका भी सामने रखा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने की कुंजी के रूप में 'LiFE' - 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली' के लिए एक जन आंदोलन भी शामिल है।
- इसे इसकी राष्ट्रीय परिस्थितियों और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (common but differentiated responsibilities and respective capabilities-CBDR-RC) के सिद्धांत पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तैयार किया गया है।
- यह कम कार्बन उत्सर्जन मार्ग की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है, साथ ही सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास भी करता है।
- अद्यतन NDC 2021-2030 की अवधि के लिए भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की रूपरेखा का भी प्रतिनिधित्व करता है।
- अद्यतन रूपरेखा, सरकार की कई अन्य पहलों के साथ, जिसमें कर रियायतें और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive scheme) जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं, भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।

- इससे नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों, इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे कम उत्सर्जन वाले उत्पादों के निर्माण आदि जैसी हरित नौकरियों में समग्र वृद्धि होगी।

2. भारत का पंचामृत और LiFE पहल

2.1. परिचय

- भारत ने UNFCCC COP-26 में अपनी बढ़ी हुई जलवायु प्रतिबद्धताओं - "पंचामृत" की घोषणा की थी। COP-26 को 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया थी।
- इसमें 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने की प्रतिबद्धता शामिल है।
- भारत द्वारा अपने नेट-शून्य लक्ष्य की घोषणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम है कि वह ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है।
- उसका ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन विश्व के कुल का मात्र 4.37% है।

2.2. पंचामृत

भारत के द्वारा तय किए गये लक्ष्य:

- 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना।
- 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना।
- 2030 तक अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन कम करना।
- 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना।
- 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचना।

2.3. LiFE पहल

- 2022 में, भारत ने मिशन LiFE आंदोलन, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लॉन्च किया, जो भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को सशक्त बनाना है।
- LiFE आंदोलन का उद्देश्य 'प्रो-प्लैनेट पीपल' (P3) नामक व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने के लिए सामाजिक नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाना है।

- प्रो-प्लैनेट लोग पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाते हैं और दुनिया भर में इसे बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता रखते हैं।
- पहल के तहत, भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक और व्यक्तिगत कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'मेरी LiFE मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया।